लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में बनेगा रक्षा उत्पादों का टेस्टिंग सेंटर

रक्षा इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की होगी स्थापना, मुफ्त दी जाएगी भूमि

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत रक्षा इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की खातिर 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने की।

डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के रूप में किया जाएगा। इसमें लखनऊ नोड के अंतर्गत स्थापित रक्षा इकाइयां उत्पादों का परीक्षण और सर्टिफिकेशन कर सकेंगी। हस्तांतरित की जाने वाली जमीन 94.20 लाख रुपये की है।

डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर में उत्पादों के परीक्षण और सर्टिफिकेशन से यूपी से रक्षा उत्पादों के निर्यात की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इससे निवेशकों को तकनीकी मदद मिलेगी और रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। इस सेंटर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर विकसित

किया जाएगा। इसे लेकर पिछले वर्ष जुलाई में उप्र. एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) और मिधानि समूह के बीच एमओयू हुआ था।

एमएसएमई और अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि यूपी रक्षा विनिर्माण और इनोवेशन का वैश्विक हब बनने के साथ ही देश के डिफेंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लखनऊ नोड डिफेंस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। यह प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सेंटर होगा।

इसका फायदा डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत स्थापित इंडस्ट्रीज को अपने उत्पाद बेहतर बनाने और सर्टिफिकेशन के बाद उत्पाद की मार्केटिंग में मिलेगा। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को समय पर पूरा कराने और संचालन के लिए यूपीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना बंद होगी

लखनऊ। पर्यटन विभाग में चल रही विश्व बैंक सहायतित यूपी प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना बंद होगी। इस परियोजना में अब तक जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर से पूरा कराएगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत पर्यटन स्थलों के आसपास गरीब विक्रेताओं की आजीविका में सुधार लाने की पहल की गई थी। ब्यूरो